बदलाव

आउटर रिंगरोड पर बाहरी राज्यों व शहरों से माल का आवागमन आसान होगा, यातायात व्यवस्था भी होगी बेहतर

छह लॉजिस्टिक पार्कों से सुधरेगी कारोबार की सेहत

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। राजधानी में लॉजिस्टिक पार्कों के साथ यहां ट्रैफिक व कारोबार दोनों की सेहत सुधारने का काम होगा। बाहरी राज्यों व शहरों से माल का आवागमन सुगम बनाने के लिए स्थानीय सड़कों के नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा। वहीं, कारोबार को बढ़ाते हुए रोजगार के नए अवसर भी बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार से निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ में भी इसे बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आउटर रिंगरोड पर छह लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने शहर की जरूरतें पूरी करने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान के रूप में कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक (सीटीसीपी) अनूप श्रीवास्तव के मुताबिक, केंद्र सरकार से सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जाएगा। पूरी कवायद मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में बनी सिटी लेवल कमेटी की निगरानी में होगी। प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा खुद प्रमुख सचिव आवास करेंगे। सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए एलडीए के अलावा नगर निगम, जिला उद्योग अधिकारी, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, यूपीपीसीबी, पीडब्ल्यूडी काम कराएंगे। पूरी कवायद सभी राज्यों के बीच माल की आपूर्ति बेहतर करने के लिए बने लीड्स फ्रेमवर्क में होगी। एक सप्ताह में सूचनाएं जुटाकर सिटी लॉजिस्टिक प्लान पर काम शुरू होगा।

कार्ययोजना में इन बिंदुओं पर होगा काम

- सिटी डेवलपमेंट प्लान में ही लॉजिस्टिक प्लान को शामिल किया जाएगा।
- सभी विभाग लॉजिस्टिक प्लान के लिए जरूरी सूचनाएं एलडीए वीसी संग साझा करेंगे। इसमें माल के आवागमन वाली जगहों की सूचना से लेकर वाहनों के उपयोग के प्रकार और सड़क मार्ग को चिह्नित किया जाएगा।
- ऐसे प्वाइंट पूरे शहर में चिह्नित होंगे, जहां माल की लोडिंग व अनलोडिंग हो सके।
- ऐसे बिंदुओं, चौराहों पर विशेष रूप से काम होगा, जो ट्रैफिक के लिए बॉटलनेक का काम करते हैं और जाम की वजह बनते हैं। इनमें सुधार किया जाएगा।
- माल के परिवहन की लागत को कैसे कम किया जाए, स्टेकहोल्डरों से बात कर इसमें कमी लाने के लिए उपाय तलाशे जाएंगे।
- लॉजिस्टिक पार्क व डिलीवरी प्वॉइंट के बीच आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निगरानी के अलावा सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो सके।
- लॉजिस्टिक के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे आंतरिक सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज चैनल, संचार संसाधन, बिजली की व्यवस्था पर काम होगा।
- शहर में मौजूद सभी पार्किंग को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
- देखा जाएगा कि किस समय, कितने माल की आवक या आपूर्ति शहर से होती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित जरूरतों के लिए कैलेंडर बनाया जाए।
- माल के आवागमन में उपयोग होने वाले वाहनों से प्रदूषण कम से कम हो। इसके लिए यूपीपीसीबी के स्थानीय अधिकारियों की मदद ली जाएगी।

सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट तीनों से आता है माल

एलडीए अफसरों का कहना है कि स्टेकहोल्डर्स से अभी तक हुई वार्ता के मुताबिक शहर में रेलवे, सड़क और एयरपोर्ट तीनों से माल आता है। ऐसे में एयरपोर्ट और रेलवे रूट को भी ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक पार्क बनाने होंगे। यह भी संभावना देखी जा रही है कि रेलवे से सभी माल एक ही स्टेशन पर आए, वहीं पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाए। इसी तरह एयरपोर्ट पर मौजूद व्यवस्था में सुधार किया जाए। पूरी कवायद अगले 30 साल को ध्यान में रखते हुए होगी।

विशेषज्ञ संस्था का होगा चुनाव

शासन से निर्देश के बाद अब एलडीए विशेषज्ञ संस्था का चुनाव लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने के लिए करेगा। संस्था का काम शहर के बाजार और उद्योगों का सर्वेक्षण कर उनकी जरूरत और मौजूदा आकार को पता करना होगा। इसका आकलन कर जरूरी संसाधन विकसित किए जाएंगे। लॉजिस्टिक प्लान तैयार करते समय एलडीए कारोबारियों से भी सुझाव लेगा।